WORLD SPIRITUALITY SUMMIT
SHANTI MANTHAN
16–17 DECEMBER 2026, BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI
REGISTER NOW →

भारत की AI रेस: डेटा सेंटर्स का मालिक कौन?

Contributed By: आचार्य प्रशांत | नवभारतटाइम्स.कॉम • 1 Nov 2026, 8:48 am IST

Subscribe YouTube 12M

मशीनें पहले से बड़ी, तेज़ और अधिक सक्षम होती जा रही हैं। लेकिन इस सारे उत्साह में एक असुविधाजनक प्रश्न दब जाता है। इन मशीनों को निर्देश कौन देगा और इनसे क्या काम करवाया जाएगा?



आचार्य प्रशांत दार्शनिक और लेखक हैं।**(फोटो- नवभारतटाइम्स.कॉम)**

भारत में आज इतने बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बनाने की घोषणाएं हो रही हैं कि कुछ साल पहले तक इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। हर नई घोषणा में हज़ारों करोड़ के निवेश, सैकड़ों मेगावाट की क्षमता, रोज़गार के अवसरों और AI की वैश्विक दौड़ में भारत के आगे बढ़ने की बातें होती हैं। मशीनें पहले से बड़ी, तेज़ और अधिक सक्षम होती जा रही हैं। लेकिन इस सारे उत्साह में एक असुविधाजनक प्रश्न दब जाता है। इन मशीनों को निर्देश कौन देगा और इनसे क्या काम करवाया जाएगा? किसी भ्रमित व्यक्ति के हाथ में पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली साधन आ जाए, तो क्या वह साधन उसे समझदार बना देगा? या उसके भ्रम को ही पहले से कहीं अधिक ताकत

आज का तापमान
नई दिल्ली
तापमान वायु गुणवत्ता
29.9°c
28 जैसा लगता है
Min 20 Max 30.7
Smoky haze
Powered By AQI

वीडियो

India China: ताइवान छोड़ भारत से क्यों भिड़ रहा चीन? माओ के 5 फिंगर का सपना पूरा...

INDIA Block Rally: राहुल, अखिलेश, ममता, प्रियंका रामलीला मैदान पहुंचे , प्रतापग...

Nazia Elahi Khan Hindu Dharma Return: नाजिया खान का सनातन में वापसी का ऐलान...

Indian Railway: दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार जाने वाली कई ट्रेनों का बदला टाइम, देखें टाइम टेबल

Pakistan Afghanistan

रेकमेंडेड खबरें

मिल जाएगी?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में डेटा सेंटरों की स्थापित क्षमता 2020 में लगभग 375 मेगावाट थी, जो अगस्त 2026 तक बढ़कर 1.57 गीगावाट पहुँच गई। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW) के एक अध्ययन का अनुमान है कि 2030 तक यह क्षमता 4.5 से 6.5 गीगावाट हो सकती है। यह भविष्य का अनुमान है, अभी स्थापित हो चुकी क्षमता नहीं। लेकिन विस्तार की दिशा स्पष्ट है। चिकित्सा, शोध, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के लिए भारत को आधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाएँ चाहिए। तकनीकी कमज़ोरी कोई गुण नहीं है। मगर मेगावाट से बिजली की क्षमता का पता चलता है, उससे यह नहीं पता चलता कि उस बिजली से कराया जाने वाला काम कितना सार्थक है। हम बड़ी तत्परता से हिसाब लगाते हैं कि मशीनें क्या-क्या कर सकती हैं, लेकिन यह जाँचने की फ़ुर्सत कम ही निकालते हैं कि उनसे काम करवाना कौन चाहता है और क्यों।

क्लाउड का भी ज़मीन पर ठिकाना है

‘क्लाउड’ शब्द ने एक बहुत ठोस सच्चाई को हमारी नज़रों से ओझल कर दिया है। किसी डेटा सेंटर में चमचमाते गलियारे हो सकते हैं, व्यवस्थित लगे सर्वर हो सकते हैं और धुआं उगलती कोई चिमनी नज़र नहीं आती। लेकिन चिप बनाने के लिए खनिज चाहिए और उनके निर्माण में जटिल औद्योगिक प्रक्रियाएँ लगती हैं। इमारतों के लिए इस्पात और कंक्रीट चाहिए। सर्वरों को बिजली चाहिए, उन्हें लगातार ठंडा रखना पड़ता है और समय-समय पर बदलना भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि प्रदूषण डेटा सेंटर के दरवाज़े पर ही दिखाई दे। हमने चिमनी को तस्वीर से बाहर रखना सीख लिया है और फिर अपनी ही तस्वीर देखकर खुश होते हैं कि कितनी साफ़-सुथरी है!



यह भी पढ़ें:
एयरफोर्स ने 104 साल के विंग कमांडर का जन्मदिन मनाकर छू लिया दिल, IAF की डेंटल ब्रांच के रहे हैं फाउंडर

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, दुनिया भर के डेटा सेंटरों ने 2025 में लगभग 485 टेरावाट-घंटे बिजली की खपत की। एजेंसी के मुख्य अनुमान के अनुसार, 2030 तक यह खपत लगभग 950 टेरावाट-घंटे पहुँच सकती है। इन आँकड़ों में सभी तरह के डेटा सेंटर शामिल हैं, केवल AI वाले नहीं। लेकिन AI-केंद्रित डेटा सेंटरों की बिजली खपत 2025 में ही लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गई। यह बिजली किसी काल्पनिक बादल से नहीं आती। इसकी आपूर्ति किसी वास्तविक बिजली ग्रिड से, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित समय में होती है। भारत में आज भी अधिकांश बिजली कोयले से बनती है। नवीकरणीय ऊर्जा के अनुबंध उपयोगी हैं, लेकिन उनसे यह साबित नहीं हो जाता कि चौबीसों घंटे इस्तेमाल होने वाली सारी बिजली स्वच्छ स्रोतों से ही आ रही है। बिजली किसी को तो बनानी पड़ेगी और उसकी कीमत भी किसी को चुकानी पड़ेगी।

Advertisement



'पूरा विपक्ष एकजुट, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार' दिल्ली की रैली से जोश ...



लेफ्ट-TMC से PDP-नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, एक मंच पर विपक्ष के धुर विरोधी दल, चुनावी मैदान...



'प्रियंका को किनारे करने की कोशिश में राहुल गांधी', INDIA गठबंधन की रामलीला मैदान रै...



2 पायलट अनिवार्य... उत्तराखंड हादसे के बाद DGCA ने चार धाम हेलीकॉप्टर सेवा के नियम कड़े...



एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया ने संभाली भारतीय वायुसेना के



यह भी पढ़ें:

दुबई लेओवर को बनाएं मिनी-वेकेशन, स्टॉपओवर वीजा से मिलेगा शहर घूमने का मौका, जानें आसान टिप्स और बेस्ट लोकेशन्स

बिजली के बाद पानी का सवाल भी आता है। डेटा सेंटरों को ठंडा रखने की अलग-अलग तकनीकें हैं। कुछ केंद्रों में परिसर के भीतर बहुत कम पानी खर्च होता है। लेकिन बिजली उत्पादन और सेमीकंडक्टर चिप बनाने में भी पानी लगता है। WRI इंडिया के अध्ययन के अनुसार, भारत के आधे से अधिक डेटा सेंटर ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ पहले से पानी का संकट है। कोई कंपनी अपने परिसर की चारदीवारी के भीतर इस्तेमाल हुए पानी का हिसाब दे सकती है। लेकिन नदी को क्या पता कि कंपनी की चारदीवारी कहाँ समाप्त होती है?

Advertisement



यह भी पढ़ें:

EPFO का बड़ा प्लान, UPI से फटाफट निकलेगा पीएफ का पैसा, सर्विस लॉन्च होने की आ गई है डेट

महाराष्ट्र के ठाणे में स्थानीय निवासियों ने एक प्रस्तावित विशाल डेटा सेंटर पर आपत्ति उठाई है। इस परियोजना की अनुमानित बिजली माँग लगभग 422 मेगावाट है और इसमें बैकअप के लिए 193 डीज़ल जनरेटर प्रस्तावित हैं। परियोजना विकसित करने वाली कंपनी अमेज़न वेब सर्विसेज़ का कहना है कि डेटा सेंटर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। कंपनी ने कुल दैनिक पानी की आवश्यकता लगभग 1,25,000 लीटर बताई है। इसमें अधिकांश पानी शोधित अपशिष्ट जल होगा, जिसका इस्तेमाल परिसर में पेड़-पौधों की देखभाल के लिए किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बुनियादी ढाँचे पर पड़ने वाले दबाव, शोर और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर सवाल उठाए हैं। कंपनी के स्पष्टीकरणों को सुना जाना चाहिए, लेकिन वे स्वतंत्र जाँच का विकल्प नहीं हो सकते।

Advertisement

आयरलैंड में 2025 के दौरान दर्ज कुल बिजली खपत का 23 प्रतिशत डेटा सेंटरों ने इस्तेमाल किया। वहाँ के नियामक ने अब नए ग्रिड कनेक्शन लेने वाले डेटा सेंटरों के लिए शर्त रखी है कि वे अपनी सालाना बिजली माँग का कम-से-कम 80 प्रतिशत आयरलैंड में अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली उत्पादन से पूरा करें। इस नियम को लागू करने के लिए कुछ समय की छूट भी रखी गई है। भारत की परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ देश की कुल बिजली खपत में डेटा सेंटरों की हिस्सेदारी अभी छोटी है। लेकिन राष्ट्रीय आँकड़ों में स्थानीय स्तर पर बिजली की बहुत बड़ी माँग छिप सकती है। और जिन लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा भी उन्हीं को मिल रहा हो।

Advertisement

इसी साल अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने संसद को बताया कि 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत केवल AI डेटा सेंटर होने के कारण किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी लेना अपने आप अनिवार्य नहीं हो जाता। अगर परियोजना भवन निर्माण या विकास की निर्धारित श्रेणी में आती है, तो उस आधार पर मंज़ूरी आवश्यक हो सकती है। पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े दूसरे नियम भी लागू होते हैं। लेकिन क्या केवल इमारत का आकार यह तय करने के लिए पर्याप्त है कि उसके भीतर लगी मशीनों के लगातार संचालन से पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

Advertisement

विशाखापट्टनम का मामला देखिए। वहाँ एक प्रस्तावित डेटा सेंटर पार्क को भवन एवं निर्माण की श्रेणी में पर्यावरणीय मंज़ूरी मिली है। इस परियोजना की अनुमानित बिजली माँग 512 मेगावाट है और इसके दस्तावेज़ों में प्रतिदिन लगभग 3,07,000 लीटर पानी की आवश्यकता बताई गई है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार के हलफ़नामे के अनुसार, उस अधिसूचना में डेटा सेंटरों के संचालन को पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए अलग से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। प्रश्न यह नहीं कि कोई जाँच हुई ही नहीं। प्रश्न यह है कि निर्माण पूरा होने के वर्षों बाद तक चलने वाली इतनी विशाल कंप्यूटिंग व्यवस्था के प्रभावों का उस जाँच में पर्याप्त आकलन होता भी है या नहीं।

Advertisement

और बात केवल पर्यावरणीय मंज़ूरी तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि हम प्रकृति के साथ कैसा संबंध रखते हैं। डेटा सेंटर की चारदीवारी के बाहर की दुनिया कोई खाली गोदाम नहीं है, जो हमारे इस्तेमाल के इंतज़ार में पड़ा हो। किसी आर्द्रभूमि का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई इंजीनियर उसके उपयोग की योजना बना पाया या नहीं। जंगल में रहने वाले पशु उस ज़मीन पर घुसपैठिए नहीं हैं, जिसे हमने अपनी सुविधा के लिए आरक्षित मान लिया है। हम अपनी कामनाओं पर तो सवाल नहीं उठाते, लेकिन प्रकृति की हर चीज़ को इस कसौटी पर कसते हैं कि वह हमारे किस काम आएगी। नदी को भी हम डेटा सेंटर ठंडा करने के लिए पानी का स्रोत मान लेते हैं, जैसे उसका अपना कोई महत्व ही न हो।

Advertisement

मशीन हमारी बेचैनी से सीख रही है

इतनी बिजली, इतना पानी और इतने संसाधन आखिर किसलिए चाहिए? हमें बार-बार बताया जाता है कि AI मनुष्य की माँगें पूरी करेगी। लेकिन ये माँगें आ कहाँ से रही हैं? किसी व्यक्ति को भूख लगी है, तो उसे भोजन

चाहिए। वही व्यक्ति पेट भर जाने के बाद भी खाता रह सकता है, क्योंकि वह बेचैन है, ऊब रहा है या अपने जीवन का सामना नहीं करना चाहता। बाज़ार दोनों तरह की खरीद को एक ही नाम देता है: माँग। बिक्री के आँकड़े यह नहीं बताते कि भोजन पोषण के लिए लिया गया था या अपने आप से बचने के लिए। माँग पूरी करने की अपनी क्षमता पर गर्व करने से पहले क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि माँग करने वाला कौन है?

Advertisement

अहंकार से मेरा अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार वह भीतर बैठा केंद्र है जो 'मैं' कहता है, अपनी पहचान शरीर, स्मृतियों, पद और संपत्ति से जोड़ता है और फिर संसार के सहारे अपने को सुरक्षित करना चाहता है। मेरे पास कुछ और आ जाए, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे पक्ष की जीत हो जाए, मुझे कभी अपने साथ अकेले न रहना पड़े, तब मैं पूरा हो जाऊँगा। एक उपलब्धि के बाद दूसरी उपलब्धि आती है, लेकिन जिस चैन का वादा था, वह आता ही नहीं। यह देखने के बजाय कि बार-बार यह वादा झूठा क्यों साबित हो रहा है, मैं उसी चैन को पाने के लिए और शक्तिशाली साधन खोजने लगता हूँ। समस्या उपलब्धि में नहीं है। समस्या यह है कि हम अपनी असुरक्षा का इलाज उपलब्धियों में खोजते हैं। और यही असुरक्षा, अगर उसकी जाँच न हो, तो एक पूरी अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है।

Advertisement

एक मनोरंजन समाप्त होते ही व्यक्ति को दूसरा मनोरंजन क्यों चाहिए? शायद वह अपने भीतर बैठे उसी बेचैन 'मैं' से कुछ देर की राहत चाहता है, जो हर अनुभव के दौरान भी चैन नहीं पाता। वह अपने ही बोझ से मुक्त होना चाहता है। लेकिन जो उस बोझ को ढो रहा है, उसकी जाँच करने के बजाय अपने को व्यस्त रखने के लिए एक और वस्तु खरीद लेता है। चाहत मुक्ति की है, लेकिन उसे पाने का तरीका बंधन और बढ़ा देता है।

डिजिटल कंपनियाँ अच्छी तरह समझ गई हैं कि इस असुरक्षा से कितना पैसा कमाया जा सकता है। कोई डिजिटल सेवा देखती है कि व्यक्ति किन बातों से उत्तेजित या परेशान होता है, किस तरह की सामग्री उसे बार-बार वापस खींच लाती है। फिर उसके सामने वैसी ही और सामग्री रख दी जाती है। उसकी असुरक्षा डेटा बन जाती है, उसका बार-बार लौटना एंगेजमेंट कहलाता है और एंगेजमेंट से कमाई होती है। ज़रूरी नहीं कि कंपनी उसे नुकसान पहुँचाना चाहती हो। लेकिन उसके असंतुष्ट बने रहने से कंपनी की कमाई बढ़ सकती है। स्टैनफ़र्ड के शोधकर्ताओं ने X की व्यक्तिगत फ़ीड का अध्ययन करके पाया कि लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर सामग्री को प्राथमिकता देने से ऐसी पोस्टों का प्रसार बढ़ सकता है जो उन्हीं उपयोगकर्ताओं के घोषित मूल्यों से मेल नहीं खातीं। जिस चीज़ पर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी को हम अपने जीवन का हिस्सा भी बनाना चाहते हों।

Advertisement

AI इस संबंध को और गहरा कर सकती है। वह किसी व्यक्ति के डर और कल्पनाओं के अनुरूप अंतहीन सामग्री तैयार कर सकती है, साथी होने का आभास दे सकती है और किसी को प्रभावित करने के तरीकों को अत्यंत व्यक्तिगत बना सकती है। मशीन केवल पहले से मौजूद इच्छा का पालन नहीं करती। वह हमारी अगली चाहत को भी आकार दे सकती है। हम अपने ही संस्कारों से एक साधन बनाते हैं और फिर उसी साधन को अनुमति दे देते हैं कि वह हमारे संस्कारों का अध्ययन करे और उन्हें और मज़बूत बनाए। एंगेजमेंट बढ़ने पर अधिक कंप्यूटिंग की माँग होती है और अधिक कंप्यूटिंग से व्यक्ति को बाँधे रखने के तरीके और सटीक होते जाते हैं। इस तरह इन मशीनों की माँग का एक हिस्सा इसलिए पैदा हो रहा है कि वे और माँग पैदा कर सकें।

Advertisement

लेकिन हमारा यांत्रिक जीवन AI के आने से शुरू नहीं हुआ। मशीनों के हमारे व्यवहार का अध्ययन करने से बहुत पहले हम अपनी आदतों के गुलाम थे। पड़ोसी जो चाहता था, हम भी वही चाहने लगते थे। समाज जिन बातों से डरना सिखाता था, हम उनसे डरने लगते थे और इस पूरी आज्ञाकारिता को अपनी स्वतंत्र पसंद का नाम देते थे।

मशीन ने हमें यांत्रिक नहीं बनाया। उसने हमें पहले से ही यंत्रवत जीते हुए पाया और अब उसी जीवन को और कुशलता से चलाने की क्षमता हासिल कर ली है। मशीन प्रलोभन हमारे सामने सजा सकती है, लेकिन उन प्रलोभनों के आगे मैं क्यों झुकता हूँ, यह देखना मेरी ही ज़िम्मेदारी है।

Advertisement

कोई व्यक्ति किसी शैक्षणिक सॉफ़्टवेयर का उपयोग विषय को समझने के लिए कर सकता है और कोई उसी का उपयोग केवल प्रमाणपत्र इकट्ठा करने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए। AI से सार्वजनिक सेवाएँ बेहतर हो सकती हैं, लेकिन सरकार उसी तकनीक का उपयोग अपनी सत्ता मज़बूत करने और जनमत को प्रभावित करने के लिए भी कर सकती है। केवल काम का नाम जान लेने से यह नहीं पता चलता कि वह किस मंशा से किया जा रहा है। मन एक अद्भुत साधन है, लेकिन वह अपने उद्देश्य का निर्धारण अपने आप नहीं करता। एक बार अहंकार ने उसे अपने काम में लगा लिया, तो बुद्धि अपना पूरा जीवन किसी मूर्खतापूर्ण आसक्ति को बचाने के लिए बड़े चतुर तर्क जुटाने में लगा सकती है। बुद्धि बता सकती है कि कोई उद्देश्य कैसे पूरा होगा। लेकिन केवल बुद्धि यह नहीं बता सकती कि वह उद्देश्य पूरा करने योग्य भी है या नहीं।

Advertisement

और खतरा केवल यह नहीं कि AI हमें गलत जवाब दे सकती है। वह बिल्कुल सही जवाब भी दे सकती है, जिनका इस्तेमाल हम अपना जीवन बदले बिना करते रहें। मैं उपभोगवाद की आलोचना करने वाला कोई बहुत अच्छा लेख पढ़ सकता हूँ, उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ, दोस्तों को भेज सकता हूँ और फिर पहले की तरह उपभोग में लग सकता हूँ। जानकारी बढ़ गई। समझ बढ़ी क्या?

मशीनों की कार्यकुशलता बढ़ाना भी अपने आप में समाधान नहीं है। अगर कोई नई चिप वही गणना करने में पहले

से आधी बिजली खर्च करे, तो इंजीनियरों ने अच्छा काम किया है। लेकिन सस्ती कंप्यूटिंग के कारण हम पहले से कई गुना अधिक गणनाएँ करवाने लगें, तो कुल बिजली की माँग फिर भी बढ़ सकती है। उपभोग को अधिक कुशल बनाकर हम कभी न समाप्त होने वाली भूख का इलाज नहीं कर सकते।

Advertisement

किसकी तरक्की, किसकी कीमत पर?

अब कोई कहेगा, 'भारत पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता।' बात ठीक है। विदेशी नियंत्रण वाली तकनीक पर निर्भर रहने से देश असुरक्षित हो सकता है। हमें वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षित बुनियादी ढाँचा चाहिए। IndiaAI पहल के अंतर्गत शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को किफ़ायती दरों पर दसियों हज़ार GPU उपलब्ध कराने का प्रयास इस दिशा में एक सार्थक कदम है। लेकिन अपने देश में डेटा सेंटर स्थापित कर लेने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि उनमें इस्तेमाल होने वाली चिप, AI मॉडल, प्लेटफ़ॉर्म या वहाँ होने वाले कारोबार के उद्देश्य भी हमारे नियंत्रण में हों। दूसरों की कंप्यूटिंग के लिए अपने यहाँ जगह उपलब्ध कराना और अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करना एक ही उपलब्धि नहीं है।

Advertisement

केंद्रीय बजट 2026-27 में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत भारत स्थित डेटा सेंटरों के माध्यम से वैश्विक क्लाउड सेवाएँ देने वाली पात्र विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर-छूट देने का प्रस्ताव रखा गया। कंप्यूटिंग सेवाओं का निर्यात करना बिल्कुल उचित है। लेकिन जब जनता की ओर से रियायतें और बुनियादी सुविधाएँ दी जा रही हों, तो जनता को उनका पूरा हिसाब भी मिलना चाहिए। निर्माण के दौरान पैदा हुए कामों के अलावा कितने टिकाऊ रोज़गार मिलेंगे? देश की अपनी तकनीकी क्षमता कितनी बढ़ेगी? बिजली ग्रिड के विस्तार की कीमत कौन चुकाएगा? मुनाफ़ा कहाँ जाएगा? और इसके लिए संसाधन लगाकर हम किन दूसरी परियोजनाओं को नहीं बना पाएँगे?

Advertisement

जितना महत्व परियोजना के आकार का है, उतना ही उसके उद्देश्य का भी है। एक अस्पताल और लोगों की व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार ध्यान भटकाने वाली सामग्री बेचने वाला डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक ही ग्रिड से बिजली ले सकते हैं। दोनों के काम का मूल्यांकन केवल उनके बिजली बिल से नहीं किया जा सकता। किसी निवेश का औचित्य हो सकता है, लेकिन उसे जाँचना पड़ेगा। पहले से मानकर नहीं चला जा सकता कि बड़ा निवेश है, इसलिए अच्छा ही होगा।

और प्रतिस्पर्धा करना एक बात है, हर हाल में दूसरों से आगे निकलने की धुन सवार होना दूसरी। पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली और हमारी अब तक संतोषजनक रही गाड़ी अचानक छोटी लगने लगी। इसी बेचैनी पर राष्ट्रध्वज लगा दीजिए, तो वही बात राष्ट्रीय नीति जैसी सुनाई देने लगती है। दूसरों पर निर्भरता कम करना आवश्यक है, लेकिन केवल इसलिए किसी से आगे निकलना कि वह हमसे आगे है, कोई समझदारी नहीं है।

Advertisement

बिजली साफ़ हो जाए, तो क्या उद्देश्य भी साफ़ हो जाएगा?

अक्टूबर 2026 में नीति आयोग ने डेटा सेंटरों के मूल्यांकन के लिए जो ढाँचा जारी किया, उसमें राज्यों से बिजली ग्रिड की तैयारी, कुल बिजली माँग, पूरे जलग्रहण क्षेत्र में पानी के संकट, पर्यावरणीय प्रभाव और सरकारी रियायतों से जनता को होने वाले लाभ का आकलन करने को कहा गया है। मंज़ूरी मिलने के बाद भी यह जाँचने की सिफ़ारिश की गई है कि संसाधनों को लेकर किए गए वादे निभाए गए या नहीं और बताए गए लाभ वास्तव में मिले या नहीं। ये आवश्यक बातें हैं। लेकिन ये दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं हैं। CEEW ने राज्य-स्तर की डेटा सेंटर नीतियों से जुड़ी पंद्रह व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। उनमें से केवल पाँच में पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ संचालन के प्रावधान स्पष्ट रूप से मौजूद थे। उद्घाटन की तस्वीरें खिंच जाने के पाँच साल बाद कौन देखेगा कि

नौकरियों, पर्यावरणीय सुरक्षा और सार्वजनिक लाभ के जो वादे किए गए थे, वे पूरे भी हुए या नहीं? किसी नीतिगत ढाँचे की सार्थकता तब सिद्ध होगी, जब उसकी कसौटी पर असफल परियोजना को बदला जाए या मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया जाए।

Advertisement

डेटा सेंटरों को चौबीसों घंटे कम कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली दीजिए। पानी कम से कम इस्तेमाल कीजिए, उपकरणों की उम्र बढ़ाइए और कचरा घटाइए। संसाधनों के उपयोग का पारदर्शी हिसाब माँगिए, स्थानीय समुदायों की रक्षा कीजिए और लोगों के मनोविज्ञान का फ़ायदा उठाकर उन्हें प्रभावित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखिए। ये सब ज़रूरी काम हैं। लेकिन अगर कोई डेटा सेंटर पूरी तरह स्वच्छ बिजली से भी चल रहा हो, तब भी पूछना पड़ेगा कि वह बिजली किस काम में लग रही है। बेहतर तकनीक से हम अपनी आदतों के कारण पृथ्वी को होने वाला नुकसान घटा सकते हैं, लेकिन केवल तकनीक से उन आदतों की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते।

Advertisement

किसी मंत्रालय का काम नागरिकों को यह बताना नहीं है कि वे क्या चाहें और क्या न चाहें। अपनी कामनाओं की जाँच व्यक्ति को स्वयं करनी होगी। कोई कानून यह काम उसके लिए नहीं कर सकता। मुझे एक घंटे का और मनोरंजन क्यों चाहिए? एक और उपलब्धि हासिल करके मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब मैं अपने भीतर किस बात का सामना नहीं करना चाहता? ऐसा नहीं कि हमें अपनी आदतों की गुलामी का पता ही नहीं होता। बहुत बार हम उसे अच्छी तरह पहचानते हैं, फिर भी सही ठहराते रहते हैं। देखना तभी सार्थक होता है जब जो कुछ झूठा दिखाई दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए भी मैं तैयार होऊँ।

Advertisement

और इस तैयारी की कीमत चुकानी पड़ती है। किसी व्यक्ति को अपना प्रिय मनोरंजन छोड़ना पड़ सकता है। किसी कंपनी को कमाई का आसान रास्ता बंद करना पड़ सकता है। किसी सरकार को ऐसी प्रतिष्ठित परियोजना से इनकार करना पड़ सकता है जिसके नुकसान उसके लाभ से अधिक हों। अपनी सारी मनमानियाँ जारी रखकर उनके परिणामों से मुक्ति नहीं माँगी जा सकती। जब अपने को ही सबसे ऊपर रखने की ज़िद कुछ ढीली पड़ती है, तो संसार से हमारा संबंध भी बदलने लगता है। नदी को केवल हमारी प्यास बुझाकर अपना महत्व साबित नहीं करना पड़ता। किसी पशु को जीने का अधिकार पाने के लिए हमारी सेवा करने की ज़रूरत नहीं रह जाती।

Advertisement

भारत शक्तिशाली तकनीक विकसित करे। उससे रोगियों को सहायता मिले, विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद मिले, वैज्ञानिकों को शोध में मदद मिले और उन सबका जीवन बेहतर हो सके जिन्हें इससे वास्तविक लाभ हो सकता है। साथ ही बिजली, पानी और जनता पर पड़ने वाले खर्च का पूरा हिसाब भी माँगा जाए। हमें बड़ी चिंता रहती है कि कहीं एक दिन मशीनें मनुष्य के नियंत्रण से बाहर न चली जाएँ। लेकिन अभी तो हम स्वयं ही अपनी ऐसी कामनाओं की सेवा में असाधारण कंप्यूटिंग शक्ति लगा रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति तक की हमने ठीक से जाँच नहीं की है। मशीनें कितनी बुद्धिमान हो गई हैं, इसका उत्सव मनाने से पहले यह तो पता करें कि उन्हें आदेश दे कौन रहा है।

(आचार्य प्रशांत दार्शनिक और लेखक हैं। उनका कार्य आत्म-अन्वेषण और समकालीन जीवन में उसके अनुप्रयोग पर केंद्रित है।)

कन्वर्सेशन शुरू करें | कमेंट पोस्ट करें

पिछला लेख

अगला लेख

India

की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद

Hindi News

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर

Some Active Trends

PM Kisan Samman Nidhi | Anant Singh News | Aaj Ka Mausam | IND vs NZ Live Score | India Playing 11 | Rajasthan Panchayat Election 2026 | Kal Ka Mausam

NBT नवभारत टाइम्स

Powered by TIMES INTERNET

Languages Sites

Kannada News | Marathi News | Malayalam News | Gujarati News | Bangla News | Samayam News | Telugu News | English News | Tamil News | Pregatips News

About

About Us | Colombia Ads and Publishing | Terms and Conditions | Privacy Policy | Work With Us | RSS

Follow Us On

This website follows the DNPA's code of Conduct

Copyright - 2024 Bennett, Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights :Times Syndication Service